भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1850
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत प्रचालित सार्वजनिक डेटा कार्यालय/सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर

1850. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रचालित सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) और सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर (पीडीओए) की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में पीएम-वाणी हॉटस्पॉट का ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ग) वाणिज्यिक ब्रॉडबैंड की ज्यादा लागत को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जिसका इस्तेमाल छोटे और मध्यम आकार के उद्यमी नहीं कर सकते, जिससे फाइबर कनेक्शन की पहुंच सीमित हो जाती है; और

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जनजातीय और दूर-दराज के क्षेत्रों, विशेषकर सोलापुर, नन्दुरबार, भंडारा, सांगली और धुले जैसे शहरों के औद्योगिक जिलों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) और सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीडीओए) की कुल संख्या निम्नानुसार है:

पीडीओ की कुल संख्या: 4,06,874
पीडीओए की कुल संख्या: 207

(ख) महाराष्ट्र राज्य में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्र सहित) पीएम-वाणी हॉटस्पॉट की कुल संख्या 34,112 है, जो नीचे दी गई है।

पीएम-वाणी वाईफाई हॉटस्पॉट (महाराष्ट्र)	**संख्या**
ग्रामीण क्षेत्र में पीएम-वाणी हॉटस्पॉट	7,266
शहरी क्षेत्र में पीएम-वाणी हॉटस्पॉट	26,846
कुल	**34,112**

(ग) प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना के अंतर्गत, सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स के प्रसार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए, मौजूदा पीएम-वाणी फ्रेमवर्क में कई अंत:क्षेपों और पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों को दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 16.09.2024 को जारी किया गया है। नीतिगत अंत:क्षेपों में से एक सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को नियमित एफटीटीएच कनेक्शन के माध्यम से पीएम-वाणी प्रदान करने की अनुमति देना था, जिससे उनकी लागत कम हो जाएगी। इसके अलावा दिनांक 16.06.2025 को, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए टैरिफ से संबंधित दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया। इस आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि 200 एमबीपीएस तक की सभी रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान को सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को संबंधित उपभोक्ता ब्रॉडबैंड मूल्य के दोगुने से अधिक टैरिफ पर ऑफर नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी)/गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु नेटवर्क बनाने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अवसंरचना को गांवों/सरकारी संस्थानों, स्कूलों और निजी क्षेत्रों सहित जीपी/ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए टीएसपी/आईएसपी को लीज़ पर दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र सहित देश के दूरस्थ, अल्पसेवित क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज सुधारने /कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों को डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।
इन जिलों में प्रदान किए गए एफटीटीएच कनेक्शन की स्थिति निम्नानुसार है:

	भारतनेट के माध्यम से प्रदान किए गए एफटीटीएच कनेक्शन की संख्या
सोलापुर	207
नंदुरबार	683
भंडारा	347
सांगली	461
धुले	305

इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में भारतनेट परियोजना के तहत 31,389 एफटीटीएच कनेक्शन भी प्रदान किए गए हैं।

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर, नंदुरबार, भंडारा, सांगली और धुले शहरों में मोबाइल कवरेज की स्थिति इस प्रकार है:

जिला	**गांवों की कुल संख्या**	**मोबाइल कवरेज सहित गांवों की कुल संख्या**	**2जी मोबाइल कवरेज सहित गांवों की कुल संख्या**	**3जी मोबाइल कवरेज सहित गांवों की कुल संख्या**	**4जी मोबाइल कवरेज सहित गांवों की कुल संख्या**	**5जी मोबाइल कवरेज सहित गांवों की कुल संख्या**
भंडारा	885	876	817	45	865	773
धुले	720	719	657	352	712	567
नंदुरबार	960	913	723	347	889	732
सांगली	724	721	698	319	719	622
सोलापुर	1159	1158	1108	164	1153	1058

*****